भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3545
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन द्वारा होटन प्रान्त में काउंटियों की स्थापना

3545. **डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय क्षेत्र को शामिल करते हुए होटन प्रांत में दो नई काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, यदि हाँ, तो इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीतिक और कूटनीतिक उपाय किए गए हैं;

(ख) इन काउंटी की स्थापना के विरुद्ध भारत द्वारा दर्ज कराए गए विरोधों का ब्यौरा क्या है और चीनी सरकार से क्या प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने अक्साई चिन क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक विकास का मुकाबला करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) भारत सरकार को चीन के होटन प्रान्त में तथाकथित दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित चीनी पक्ष की घोषणा की जानकारी है। इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में आते हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के भारतीय भूभाग पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नए काउंटी के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक और सतत स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। भारत सरकार ने राजनयिक माध्यमों से इन घटनाक्रमों पर अपना गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास कर रहा है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु अवसंरचना के सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और साथ ही भारत की सामरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

पिछले दशक (2014-2024) में सीमा अवसंरचना के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। अकेले सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पिछले दशक की तुलना में तीन गुना अधिक व्यय किया है। सड़क नेटवर्क की लंबाई, पुलों और सुरंगों की संख्या में पहले की अवधि की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई है। इससे स्थानीय आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करने और हमारे सशस्त्र बलों के लिए बेहतर सांभर-तंत्रीय सहायता प्रदान करने में सहायता मिली है।

सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है तथा अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

*****